Need for extension of Pradhan Mantri Awas Yojana in Chhattisgarh

श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत (कोरबा) : सभापति महोदय, मैं प्रधान मंत्री आवास योजना पर बात करना चाहती हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार के वर्ष 2024 और 2025 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार साढ़े आठ लाख आवास के अनुरूप साढ़े पांच लाख आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें से दिसम्बर, 2024 तक मात्र 6 प्रधान मंत्री आवास बनाए गए हैं। प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख आवास बनाने की मोदी जी की जो गारंटी थी, उसको विधान सभा चुनावों में प्रमुखता से लिया गया था और यहां पर मैं बताना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार, केन्द्र सरकार और प्रधान मंत्री जी की जो घोषणाएं हैं, उनको छत्तीसगढ़ सरकार कितनी गंभीरता से लेती है, उसे मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहती हूँ।

हमेशा यह कहा जाता रहा है कि कांग्रेस सरकार क्या करती रही है? लेकिन अभी डेढ़ साल पहले तक जब हमारी सरकार थी? (व्यवधान)

माननीय सभापति: आपकी मांग क्या है?

श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत: सर, आप मेरी बात सुन तो लीजिए। सर, मैं आँकड़े देना चाहती हूँ।? (व्यवधान) आप मेरे आँकड़े तो सुन लीजिए।

HON. CHAIRPERSON: There is a time constraint. You will not decide how much time I will give you.

? (Interruptions)

श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत: सर, आप मुझे एक मिनट तो दीजिए। मैं यह बताना चाहती हूँ कि जब हमारी सरकार थी तो हमारी सरकार ने वर्ष 2019-20 में 1 लाख 51 हजार की जो स्वीकृति थी, उसमें से 1 लाख 36 हजार की स्वीकृति दी गई थी। वर्ष 2020-21 में भी इसी प्रकार से 1 लाख 25 हजार की स्वीकृति दी गई थी। इसी तरह से हमारी सरकार के समय सभी लोगों को घर मिले, लेकिन यहां पर सिर्फ 6 आवास बने हैं तो आप इसे गंभीरता से लीजिए। हम चाहते हैं कि सभी हितधारकों को, जिनको हमारे प्रधान मंत्री जी घर देना चाहते हैं, उनको पूर्ण लाभ मिले।